

**Mr. Speaker:** Has that ship reached here or not?

**Shri Manubhai Shah:** The hon. Railway Minister may be able to say.

**श्री मनुभाई शाह :** हमारा सरस्वती नाम से एक जहाज था जिसके बारे में पाकिस्तान कह रहा है कि वह उसका घोरिजिनल घोनर है। सरस्वती नाम को रिसफियर करके उसकी जगह रजिया नाम लिख दिया गया है। रजिया नाम का जहाज जिस के बारे में आज पाकिस्तान यह कह रहा है कि घोरिजिनल घोनरशिप उसका है, हमारा नहीं इस मामले में सरकार की क्या राय है और क्या उस जहाज को वापिस लेने का इंतजाम किया जाएगा ?

**श्री मनुभाई शाह :** उसकी भी चर्चा की जाएगी।

**Shri Indrajit Gupta:** Although we have hopes and expect that all these confiscated goods will be released and restored to the original owner, may I know what is the position in law regarding the claims of compensation which may lie against both countries from the private owners in view of the fact that there has been a long delay?

**Mr. Speaker:** Legal opinion cannot be asked, only information about facts.

**Shri Indrajit Gupta:** A high powered delegation is going.

**Mr. Speaker:** Not law points.

**Shri E. Ramanathan Chettiar:** Apart from the seizure of goods, what other subjects does the Commerce Minister intend to discuss with his counterpart in Pakistan?

**Shri Manubhai Shah:** That is what I have said—to restore and normalise trade relations and to expand them in future as good neighbours and mutual friends in the same way as we are doing with the other countries, much

more so with Pakistan because it is so near to us.

### Untouchability

+

\*209. **Shri Yashpal Singh:**  
**Shri Gulshan:**  
**Shri Bata Singh:**  
**Shri Siddiah:**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether 'Untouchability' is still in existence in India even after a number of years since the Parliament banned it;

(b) if so, in what places 'Untouchability' is prevailing today;

(c) what steps Government have taken to enforce the law banning the untouchability in those areas and what were the results of such steps; and

(d) what steps Government propose to take against those who still indulge in 'Untouchability'?

**The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar):** (a) and (b). Untouchability has been disappearing noticeably from urban areas, but instances still occur in the rural areas.

(c) and (d). Government have impressed on the State Governments and Union Territories Administrations that they should tighten up the administration of the Untouchability (Offences) Act, 1955. A Committee has also been appointed *inter alia* to go into the whole question of untouchability and suggest measures to completely eradicate it. The Report of the Committee is awaited.

**श्री बागड़ी :** मेरा ब्यवस्था का प्रश्न है नियम 41 उपधारा 2 के अन्तर्गत। जो सवाल पूछा गया है उस में चार भाग हैं अर्थात् क्या देश में झूतछात अभी तक अल्प हो सकी है, और यदि नहीं तो कहाँ कहाँ। कानून को लागू करने के लिये सरकार क्या कर रही है और उस के बाद यह कि जो लोग झूत छात करें उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही

है। यह सारे देश का एक बुनियादी सवाल है लेकिन इसका जवाब मंत्री महोदय ने इतना मोल मोल दिया है कि चारों बातों में से किसी का जवाब नहीं आ सका। मैं इस नियम के अन्तर्गत आपकी शरण चाहता हूँ। हमको बतलाया जाये कि कानून का कितना उपयोग किया गया और किस प्रान्त में कितने मुकदमे हुए और छूतछात जो है उसका कारण क्या है। अगर इस तरह से अपूर्ण उत्तर प्रश्नों का दिया जायेगा तो लोक सभा का काम कैसे चलेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** एक बात मैं पहले अर्ज कर दूँ कि एक सवाल किया जाता है उस का जवाब दिया जाता है। लेकिन मैं चन्द दिनों से देख रहा हूँ इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। पहले पहल तो बर्दाश्त भी किया मैंने लेकिन एक रूल ऐसा मिल गया है कि जो चाहता कह देता है कि मैं रूल 41 में इन्फार्मेशन चाहता हूँ और प्वाइंट आफ आर्डर उठा देता है।

**श्री हुकन चन्ब कट्टवाय :** उनको अमृतधारा मिल गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** अमृतधारा या सरल सूटी ...

**श्री बागड़ी :** यह अमृतधारा या सरल सूटी का सवाल नहीं है ...

**अध्यक्ष महोदय :** पहले मुझे कह लेने दीजिये। आप यह तो कह सकते हैं कि सवाल का जवाब नहीं आया लेकिन इस नियम के नीचे प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं तो यह चीज यहाँ पर झलाई नहीं करती। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कहां कहां छत छत है, अगर यह इतना आप के पास हो तो दे दीजिये।

**Shri D. C. Sharma:** When anybody raises a point of order like this, it should not be attended to.

**Shri Shinkre:** Let the supplementaries come first.

**श्री मधु लिमये :** अध्यक्ष महोदय, (सी) भाग का जवाब आ सकता है।

**Shrimati Chandrasekhar:** Hon. Members are aware of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I can quote extracts from the annual reports.

**Mr. Speaker:** That is right.

**श्री : क्षप ल सिंह :** क्या सरकार ने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब तक पोलिटिकल, स्विफ्टर से अमटचेबिलिटी दूर नहीं होती तब तक समाज में से वह दूर नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने चीफ मिनिस्टर हरिजन हैं, कितने अम्बेसेडर हरिजन हैं और कितने साधु समाज के मेम्बर हरिजन हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** इस का जवाब सरकार कैसे दे सकेगी। आप साधु समाज को भी बीच में लाना चाहते हैं ?

**श्री यक्षपाल सिंह :** साधु समाज हम में सब से ऊँची जमात मानी जाती है। नन्दा जी उस के भक्त हैं इस लिये इस का जवाब दे दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप कोई और सवाल करना चाहते हैं ?

**श्री : दाशाल सिंह :** मैं जानना चाहता हूँ कि कितने केमेजु ऐसे हैं जिन में अमटचेबिलिटी के लिये पनिशमेंट दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** ये सारे फिगर्स कमिश्नर की रिपोर्ट में हैं उसे आप देख लीजिये।

**श्री बागड़ी :** जो भी पूछते हैं इसके लिये वह कह देते हैं कि नहीं मालूम। इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

**Mr. Speaker:** Are there figures available with the hon. Minister?

**Shrimati Chandrasekhar:** Yes, Sir. Up to 1964, I have got some figures.

In 1964, the number of cases convicted are 157; in 1963, 77, and so on. If figures are wanted from 1955, I can give.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रब क्या आप बोलते ही चले जायेंगे ?

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय मजबूर कर रहे हैं जबकि मुकम्मिल न दे कर । जब पूछा जाता है तब भी नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रब आप बैठ जाइये और कारवाई चलने दीजिये ।

श्री यशपाल सिंह : मैंने एक ही सवाल किया है, दूसरा नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने दोनों कर लिये ।

**Shrimati Savitri Nigam:** In view of the fact that untouchability is still prevailing in the rural areas, and the number of convictions is very very poor comparatively. I would like to know what arrangement has been made by the Government to provide legal help to the people who are really suffering and who want to get justice.

**Shrimati Chandrasekhar:** We are very much aware of this evil that is still persisting not only in the rural areas, but also in the urban areas. That is why in the backward class sector, for the scheduled castes the allotment has been increasing; from Rs. 9 crores in the first plan, it is expected to be Rs. 68 crores in the fourth plan. For legal aid, we have allotted funds to the State Governments to give legal aid to the members of this community to fight this evil. I too feel very strongly about this existing evil. That is why we have appointed in 1965 committee, which I mentioned in the main answer—the Untouchability Committee—which will go into details and submit a report to us, after which we will take steps to eradicate this evil.

श्री तुकम चन्द कछवाय : मैं स्वयं हरिजन हूँ, मुझे इस बात का अनुभव है कि सरकार ने जो कानून बनाये हैं उन के कारण अभी तक कोई घरसर इस बारे में नहीं पड़ा है । छूत छान वैसे ही कायम है । तो क्या सरकार कोई वैज्ञानिक ढंग ढूँढ़ने जा रही है जिस में कि छूत छान समाप्त हो जाये । अभी बतलाया गया है कि राज्य सरकारों को पैसा दिया गया है । राज्य सरकारों ने ठीक ढंग से पैसा खर्च नहीं किया है, क्या इस बात की कोई शिकायत मिली है ?

**Shrimati Chandrasekhar:** We have not received any complaint as regards nonutilisation of the money meant for this purpose, excepting than we ourselves are aware of the funds not being fully utilised in certain cases, where the matching grant from the State Governments has to be given.

श्री तुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं बतलाया ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है । मैं खुद सवाल पर हैरान था । क्या कोई कम्प्यूटर लगा दिया जाये इसके लिये ?

**Shri Thimmalah:** The minister stated that instances of observance of untouchability occur in rural parts. This means that the government is feeling shy of admitting that untouchability exists fully in the rural parts. May I know whether the government is prepared to show at least one dozen villages in any part of the country, in any district of any State where untouchability has completely vanished, so that Members of Parliament may visit those villages?

**Mr. Speaker:** The question should not be so long. Only the first question need be answered whether government can point out half a dozen villages where untouchability does not exist.

**Shrimati Chandrasekhar:** As the House is aware, the Untouchability Offences Act, 1955 is to be implemented by the State Governments. From the information from State Governments, I can say that in Assam Manipur and Tripura it is not a great problem at all and in West Bengal too, comparatively less. In Orissa, it is not so rigid. Even granting that there is not a single State which is free from this evil, we know of certain villages which are free from it and the State Governments are taking steps to give awards to certain villages which do not observe untouchability at all.

**Shri Shivananjappa:** May I know the number of prosecutions launched under the Untouchability Act in 1965?

**Shrimati Chandrasekhar:** For 1965 I have not got the figures.

श्री मधु लिमये : जहाँ तक छूत छात का सवाल है, इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि ग्रामों में हरिजनों के रहने के लिये सब से गन्दा और छोटा सा इलाका मिलता है, बरसात में उनमें पानी भर जाता है, साथ साथ पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है। वहाँ पर सर्वान् हिन्दुओं के जो कुएं होते हैं, कानून में लिखा है कि हरिजन वहाँ से पानी भर सकते हैं, लेकिन वह भर नहीं पाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि देहाती इलाकों में घर बनाने के लिये अच्छी जमीनों आदि की मदद और साथ साथ पीने का पानी देने के लिये सरकार क्या करेगी जिस से कि भ्रष्टपूयता के जो खतरनाक नतीजे हैं वह खत्म हो जायें।

**Shrimati Chandrasekhar:** Sir, the House is aware that the nature of this evil which is prevailing is such that the process of eradication will be a long drawn-out one. That is why from the First Plan onwards up till today we are having special schemes with special funds allotted for attending to this. As regards housing difficulties we are aware of that and that is why we have allocated funds for houses to be built for the Harijans

in certain areas. The problem is so big that it is not easy to tackle it very soon.

**Shri Vasudevan Nair:** In view of the fact that inter-caste and inter-communal marriages will help very much in solving this problem, may I know whether there is any scheme with the Government to help the couples who have entered into marriages on this basis? At least I know in my State there are certain measures taken by the Government. I want to know whether there is any scheme with the Government of India and whether the Government of India have thought about this matter.

**Mr. Speaker:** To help the couples?

**An hon. Member:** We are old.

**Mr. Speaker:** Not Shri Vasudevan Nair.

**Shrimati Chandrasekhar:** There is no ban on such things from the Government side.

**Shri Vasudevan Nair:** I want to know whether there is any conscientious effort on the part of the Government of India.

**Mr. Speaker:** Not by the Government.

श्री मोर्य : जो प्रश्न यहां पर हुए छुआछूत के संबंध में और उनके उत्तर जो मंत्री महोदय ने दिये उनसे यह साफ जाहिर होता है कि देश के कोने कोने में छुआछूत हो रही है। जितने भी छुआछूत करने वाले लोग हैं हालांकि वह जानते हैं कि छुआछूत करना एक पुलिस दस्तन्दाजी का केस है लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस दस्तन्दाजी केस नहीं बनते और वह इससे प्रकट होता है कि जो नम्बर है हालांकि देश के कोने कोने में छुआछूत होती है पर दो सौ चार सौ केस ही छुआछूत के आते हैं, तो इस बात को निगाह में रखते हुए क्या सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि हर जिले में जो हरिजन सहायक ग्रफ़्स्टर है उनको एग्जीक्यूटिव पावर भी पाय और उनको केस

चालात करके की शक्ति दी जाय जो कि वहाँ पर एक दरोगा को दी जाती है ?

**Shrimati Chandrasekhar:** Sir, I again repeat that we have appointed a Committee consisting of mostly of Members of Parliament.

**Mr. Speaker:** He wants to know whether there is a proposal to invest those local Harijan officers there with those powers so that they might challan such breaches?

**Shrimati Chandrasekhar:** These suggestions, I am sure, will be contained in the report that we will receive from the Committee. After we receive their report we will give thought to that recommendation.

**श्री यशपाल सिंह :** सरकार यह बतला सकती है कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हरिजन आत्मसात कर लिये जायेंगे, मिला लिये जायेंगे और दूसरी तरफ भ्रमण भ्रमण हरिजन छात्रावास, हरिजन मन्दिर, हरिजन बोर्डिंग हाउस, हरिजन कुएं तैयार किये जा रहे हैं, तो जब यह भ्रमणगाव की नीति है तो कब तक आत्मसात हो पायेंगे और सरकार क्यों नहीं रोकती, क्यों मिनिस्टर लोग जा जाकर उद्घाटन करते हैं हरिजन छात्रावासों का, क्यों नहीं वह आत्मसात कर लिये जाते ?

**Shrimati Chandrasekhar:** The hon. Member is a little outdated. We have already changed the pattern. We do not want any separate hostels for the Harijans. We want general hostels to accommodate Harijan boys and girls. Also, other people from the general public are given scholarships to be housed in Harijan hostels.

**Shri Bade:** Is it a fact that the followers of Dr. Ambedkar are not considered Harijans and whenever cases come up in the Board they are asked whether they are Buddhists or Hindus and when they say that they are Jains or they are Buddhists then the cases are dismissed and they are acquitted? Is it a fact that they are not considered Harijans?

**Shrimati Chandrasekhar:** The hon. Member, I suppose is not aware that untouchability is practised only in the Hindu religion and Sikh religion. People who belong to other religions do not practise untouchability.

**श्री बागड़ी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भारत के अन्दर सैकड़ों सालों से कुछ लोग समाज के मालिक हैं और बाकी समाज के अन्दर जाति-पाति के नाते से उन लोगों की जिन्दगी पशुओं से बदतर है और यही बार बार देश की गुलामी का कारण बना है, तो क्या सरकार इस आकाश और पाताल के भेल के वास्ते, जो कि ऊपर और नीचे हैं उनके भेल के वास्ते और इस छुआछूत के मिटाने के वास्ते जिन कुकर्मों की बिना पर यह छुआछूत है जैसे भंगी का पेशा जिसमें सिर पर टट्टी की टोकरी रख कर ले जाना होता है और या और दूसरे दलित जातियों के काम जिनको कि देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो मानवता का काम न हो, क्या ऐसे कामों को वैज्ञानिक ढंग से करने का और दूसरे जो आर्थिक कमी है...

**अध्यक्ष महोदय :** पहले यह सवाल खत्म हो जाय..... (अध्यक्षान).... अब आप फिर कहेंगे कि जब आप बोलते हैं तो मैं टोकता हूँ.....

**श्री बागड़ी :** अब मैं खत्म कर रहा हूँ ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप कहाँ खत्म कर रहे हैं, कितनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वह खत्म नहीं हो रहा है ।

**श्री बागड़ी :** मेरा सवाल है कि क्या ऐसे धंधे जिनसे छुआछूत स्वाभाविक है जैसे भंगी का टोकरी सिर पर ले जाना वगैरह इनके लिये म्युनिसिपैलिटीज वगैरह में ऐसी सुविधा सरकार दे रही है जिससे यह काम मानवीय ढंग से हों, छुआछूत मिटे और आर्थिक असमानता मिट जाय ?

**Shrimati Chandrasekhar:** In addition to the ceaseless effort on the part of the Government, we should

also receive co-operation from the public to do away with this evil. Because, in spite of the Act, in spite of the special funds we still find the condition continues to be deplorable. Regarding scavengers and sweepers, Government are aware of this evil of carrying nightsoil as headload. The Malkani Committee report refers to this. We are providing funds for having wheel-barrow to carry nightsoil.

**Shri A. P. Sharma:** The hon. Minister has just now stated that there is allotment of some funds for legal aid to these people. Who is in charge at the district and block level for helping Harijans needing legal help?

**Shrimati Chandrasekhar:** The district welfare officers look after this.

**श्री तुलशोबास जाधव :** इस छुआछूत को मिटाने के लिए, यह जो अधिकारी लोग जाते हैं वह अधिकारी बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, तो जैसे गांधी जी हरिजन बस्ती में जाकर रहते थे उससे लोगों को मालूम होता था कि यह नीच लोग नहीं हैं, यह ऊपर के लोग हैं उसी रीति से ग्राम सेवक से लेकर ऊपर के अधिकारी तक और मिनिस्टर तक उन लोगों में जा कर रहें और उन्हीं के साथ खाना पीना करें, ऐसा इन्तजाम सरकार करेगी या नहीं ?

**Shrimati Chandrasekhar:** It is a suggestion for action.

#### Release of U.S. Aid Cargo

+

- \*210. **Shri K. N. Tiwary:**  
**Shri P. C. Borooah:**  
**Shri P. R. Chakravarti:**  
**Shri Narayan Reddy:**  
**Shri Lahtan Chaudhry:**  
**Shri Onkar Lal Berwa:**  
**Shri Rameshwar Tantia:**  
**Shri Himatsingka:**  
**Shri Yashpal Singh:**  
**Shri Bagri:**  
**Shri Kishen Pattanayak:**  
**Dr. Ram Manohar Lohia:**  
**Shri Utliya:**  
**Shri Subodh Hansda:**  
**Shri S. C. Samanta:**

**Shri Bhagwat Jha Azad:**

**Shri M. L. Dwivedi:**

**Shri Hukam Chand**

**Kachhavaia:**

**Shri Bado:**

**Shri Vishwa Nath Pandey:**

**Shri C. K. Bhattacharyya:**

**Shri Basumatari:**

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to the U.S. request to release unilaterally the U.S. Aid Cargo which was destined for Pakistan and detained by India;

(b) if so, how much of cargo has been released; and

(c) the reaction of the Government of Pakistan thereto?

**The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah):** (a) We have agreed to release all such Aid Cargoes. Pakistan has also agreed to release all Aid Cargoes irrespective of the country of origin. All our affected importers and exporters have been sending us full details about aid cargoes and other impounded cargoes.

(b) A part of such Aid Cargoes valued at about Rs. 1 crore has been released by us and Pakistan has also released a part of such cargo.

(c) Pakistan and India have welcomed these steps.

**Shri K. N. Tiwary:** May I know whether the request for release has been received only for US Aid Cargo or for cargo from other countries as well and, if so, which are those countries and what action has been taken on this?

**Shri Manubhai Shah:** It covers all countries, irrespective of destination. Rs. 1 crore worth of such cargoes have been released.

**Shri K. N. Tiwary:** What is the total US Aid Cargo meant for India detained by Pakistan and the categories of cargo.

**Shri Manubhai Shah:** It is generally machine tools and aid for various charitable and educational institutions. The value is about Rs. 2½ crores according to our estimates.